बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या

809. **श्री ईश दत्त यादव :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार, बेरोजगार व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या क्या है ;

(ख) उन पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों जिन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, की राज्य वार संख्या क्या है और उनका पंजीकरण का वर्ष कौन-कौन सा है ; और

(ग) सरकार इन बेरोजगार व्यक्तियों को शीघ्र रोजगार उपलब्ध कराने के लिये क्या प्रयास कर रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) 30-9-1994 की स्थिति के अनुसार बेरोजगार व्यक्तियों के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं । नवीनतम राज्यवार अनुमान वर्ष 1987-88 से संबंधित हैं जो विवरण-**I** में दिए गए है **(नीचे देखिये)**

(ख) 30-9-1994 की स्थिति के अनुसार देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, विवरण-**II** में संलग्न हैं । **(नीचे देखिये)** पंजीकरण की तिथि के अनुसार श्रेणीकृत रोजगार चाहने वालों की संख्या संबंधी आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं किया जाता ।

(ग) आठवीं योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया गया है योजना की रोजगार नीति में ऐसे सैक्टरों, सब सैक्टरों तथा क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि सहित अर्थ-व्यवस्था के विकास की उच्च दर पर विचार किया गया है जिसमें रोजगार सृजन की गति को बढ़ाने के लिए उच्च रोजगार संभावनाएं हैं ।

विवरण I

बालू साप्ताहिक स्तर (1987-88) के आधार पर बेरोजगार व्यक्तियों के राज्यवार अनुमान

राज्य/संघशासित प्रदेश	बेरोजगार व्यक्तियों की अनुमानित संख्या (हजार में)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	1490
असम	282
बिहार	942
गुजरात	563
हरियाणा	349
हिमाचल प्रदेश	64
जम्मू और कश्मीर	125
कर्नाटक	569
केरल	1718
मध्य प्रदेश	648
महाराष्ट्र	1091
मणिपुर	2
मेघालय	2
नागालैण्ड (शहरी क्षेत्र)	2
उड़ीसा	614
पंजाब	293
राजस्थान	709
सिक्किम	3
तमिलनाडु	1974
त्रिपुरा	32
उत्तर प्रदेश	1218
पश्चिम बंगाल	1430

1	2
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2
अरुणाचल प्रदेश	4
चंडीगढ़	20
दादरा और नगर हवेली	1021
दिल्ली	120
गोवा, दमन और दीव	39
लक्षद्वीप	3
मिजोरम	0
पाण्डिचेरी	40
अखिल भारत :	14354

टिप्पणियां : 1. साप्ताहिक स्तर अवधारणा के अनुसार, बेरोजगार व्यक्ति वह है जिसे कार्य हेतु उपलब्ध होने पर भी संदर्भ सप्ताह के दौरान एक घंटे का भी कार्य न मिला हो।

2. 1981 तथा 1991 जनगणना जनसंख्या आंकड़ों का प्रयोग करते हुए 1 जनवरी, 1988 की अनुमानित जनसंख्या पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण—43वें दौर (साप्ताहिक स्तर) की दरों का अनुप्रयोग करके बेरोजगार व्यक्तियों के अनुमान लगाए गए हैं।

3. "नग" नगण्य के लिए है।

4. 1987–88 के राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख तथा कारगिल जिले तथा नागालैंड के ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया था।

विवरण–II

30–9–1994 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या

(हजार में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	30–9–94 की स्थिति के अनुसार चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या
1	2
राज्य	
आन्ध्र प्रदेश	2945.0
अरुणाचल प्रदेश	0.6
असम	1381.2
बिहार	3576.3
गोवा	118.6
गुजरात	218.2
हरियाणा	673.7
हिमाचल देश	527.7
जम्मू और कश्मीर	40.2
कर्नाटक	1674.0
केरल	4157.7
मध्य प्रदेश	2043.3
महाराष्ट्र	3423.4
मणिपुर	254.0
मेघालय	26.8
मिजोरम	42.9
नागालैण्ड	32.4

1	2
उड़ीसा . .	84.1
पंजाब . .	589.0
राजस्थान . .	344.4
सिक्किम . .	*
तमिलनाडु . .	3879.1
त्रिपुरा . .	102.7
उत्तर प्रदेश . .	234.4
पश्चिम बंगाल . .	497.9
संघ शासित प्रदेश	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह . .	9.2
चण्डीगढ़ . .	138.9
दादरा और नगर हवली .	4.0
दिल्ली . .	95.7
दमन और दीव .	2.2
लक्षद्वीप . .	8.3
पाण्डिचेरी . .	142.2
योग :	3695.1

टिप्पणी : 1. *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा।

2 यह हो सकता है कि क्रमांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खायें।

क्रमांकों श्रम संबंधी योजनाएं

810. **चौधरी हरमोहन सिंह :**
श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम संबंधी योजनाओं को मॉनीटर नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन योजनाओं को मानीटर किया गया और किन-किन योजनाओं को मॉनीटर नहीं किया गया ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग ने रोजगार, प्रशिक्षण, औद्योगिक संबंध, श्रमिक शिक्षा, महिला और बाल श्रम, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, श्रम कल्याण, श्रम सांख्यिकी, श्रम अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित कई योजनाएं अनुमोदित की हैं। योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति की नियमित रूप से मंत्रालय में प्रतिमाह मॉनिटरिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त, वार्षिक योजना बैठकों और अर्द्ध वार्षिक समीक्षा बैठकों में भी योजना आयोग द्वारा इन योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है।

Interim relief for working journalist

811. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-items published in the Hindistan Times dated the 17th Novermber, 1994 captioned "AINEF seeks 25 per cent interim relief" for all working journalists from March, 1992;

(b) whether Government have so far issued any notification and also referred the issue of interim allowance to the newly constituted wage boards which may after considering it, send their reports to the Labour Ministry; and

(c) if so, when the orders were issued and whether the city compensatory allowance with a minimum of Rs. 500/-per month as demanded by the All India Newspaper Employment Federation (AINEF) also covered under above Government Notification and if not, the reasons therefor?